



RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 193
दि. 14.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम मोदी बोले: निर्यात को बढ़ावा देने के फैसले से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को मिलेगा बल

नई दिल्ली (जीएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देंगे। बता दें कि बुधवार को हुई बैठक में निर्यात प्रोत्साहन मिशन और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' और 'निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना' को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सुनिश्चित

कर रहे हैं कि 'मेड इन इंडिया' की गुंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे! कैबिनेट ने 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' को मंजूरी दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, एमएसएमई, नए और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम-आधारित तथा प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 'निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना' से व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति मिलेगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत करने का भी फैसला लिया है। ये सभी खनिज हरित ऊर्जा के



लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह निर्णय स्थिरता

और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी

और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।' इन फैसलों से सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाए बल्कि वैश्विक बाजार में 'मेड इन इंडिया' की पहचान को और सशक्त बनाए। इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अस्पताल से धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने की वजह आई सामने, बेटे सनी और बाँबी ने मानी इनकी बात, डॉक्टर ने बताया सच हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। हाल ही में वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ

बढ़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों के अनुसार, कुछ समय के लिए उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। हालांकि, 12 नवंबर को उनकी तबीयत में सुधार देखने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉ. प्रतिभ समदानी ने बताया कि धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करने का निर्णय उनके परिवार की इच्छा पर लिया गया।

ने गुरुवार को निर्यातकों के लिए ₹45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। इन योजनाओं का उद्देश्य अमेरिका में बड़े शुल्कों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को राहत देना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने ₹25,060

करोड़ के 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' को मंजूरी दी है, जो भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। इसके साथ ही, ₹20,000 करोड़ के 'क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स' (सीजीएसई)

के तहत बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय गृह नमस्ती ने कहा कि यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

नतीजों से पहले ही जेडीयू के खेमे का जोश हाई, 'टाइगर जिंदा है' के लगे पोस्टर

(जीएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही पटना में पोस्टर लगने लगे हैं। महागठबंधन के नेता जहां एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए नेताओं का जोश हाई है। पटना में अभी से पोस्टर वार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के समर्थकों ने 'टाइगर अभी जिंदा है' का पोस्टर लगाया है। जेडीयू कार्यालय के सामने यह पोस्टर लगाया गया है जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

विधानसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। ईवीएम और वीवीपैट को दो लेयर की सुरक्षा में रखा गया

सीएम योगी ने जनजाति भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ, बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ (जीएनएस)। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जनजाति समाज को अपनी परंपरा, गौरव पर अनुभूति हो और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो इस कोशिश में यह उत्सव किया जा रहा है। इस उत्सव में 22 राज्यों के जनजाति समाज के कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्सव में सांस्कृतिक समागम

और यात्रा के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पार्टनर राज्य होने के साथ ही अन्य राज्यों के कलाकार यूपी में आकर इसके सहभागी बन रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने के साथ ही बिरसा मुंडा की जयंती के 150 साल पूरे होने का वर्ष भी है। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश का वर्ष भी है। वह अमरगीत जिसने स्वाधीनता को नया मंत्र दिया था। यह वर्ष भारत के संविधान, एकता और अखंडता की आत्मा बन गया है।

पुलिस भर्ती में जनजाति समाज के लोगों को मिला मौका मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के पक्षधर थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने के साथ ही बिरसा मुंडा की जयंती के 150 साल पूरे होने का वर्ष भी है। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश का वर्ष भी है। वह अमरगीत जिसने स्वाधीनता को नया मंत्र दिया था। यह वर्ष भारत के संविधान, एकता और अखंडता की आत्मा बन गया है।

पुलिस भर्ती में जनजाति समाज के लोगों को मिला मौका मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के पक्षधर थे।

राजमार्गों तथा नगरों-महानगरों के सड़क मार्गों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किए जाएगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तथा मुख्य सचिव की उपस्थिति में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिशानिर्देश

गांधीनगर, 13 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं कि राज्य में राजमार्गों तथा नगरों-महानगरों में सड़क मार्ग कार्यों की गुणवत्ता से कम्प्रोमाइज या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई तथा मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की उपस्थिति में आयोजित बैठक में ये दिशानिर्देश दिए। बैठक में महानगरों के महापौर, महानगर पालिकाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, महानगर पालिकाओं के आयुक्त



तथा क्षेत्रीय महानगर पालिका आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने अपने नगरों-महानगरों की सड़क मार्गों की स्थिति का विवरण दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जब से शासन दायित्व

संभाला है, तब से राज्य में सड़क मार्गों-पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर निरंतर बल दिया है।

ऐसे जन हित के कार्यों में क्वालिटी में कम्प्रोमाइज या समझौता करने की बात बर्दाश्त नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री ने अनेक बार इसकी प्रतीति भी कराई है। हाल ही में 3 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है।

इतना ही नहीं, हल्की गुणवत्ता के कार्य करने वाले 13 से अधिक ठेकेदारों को इस वर्ष ब्लैक लिस्ट करने तक के कड़े दंडात्मक कदम भी मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर उठाए गए हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार दोपहर को आयोजित इस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों पर के पोर्टहोल्स भरने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।

इतना ही नहीं; सम्बद्ध अधिकारी, मनुष्य आयुक्त व उपायुक्त नियमित रूप से फील्ड विजिट कर कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करते रहें और 30 नवंबर तक सड़क मार्गों की समग्र स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुलों के कार्य हो रहे हों, वहाँ डाइवर्जन

के लिए आरसीसी रोड बने, जिससे सम्बद्ध कार्य पूरा होने तक नागरिकों को परिवहन में कोई असुविधा न हो। इसके लिए भी उन्होंने बैठक में सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रभावी मंत्रियों को उनके जिलों में सड़कों की स्थिति की सम्बद्ध अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 30 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

श्री पटेल ने इस उच्च स्तरीय बैठक में यह भी कहा कि जो सड़क मार्ग मेट्रोसे गारंटी पीरियड में टूट जाएँ, उनके ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस बैठक में कहा कि शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मार्केट जैसे स्थलों, जहाँ लोगों की अधिक आवाजाही रहती हो, वहाँ शहरी प्रशासन तथा सड़क एवं भवन विभाग इस तरह सड़क मरम्मत के कार्य करें, जिसकी लोगों को अनुभूति हो। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क मरम्मत को लेकर मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निरावण, साथ ही साथ अन्य मरम्मत एवं नए सड़क निर्माण कार्य भी होते रहना जरूरी हैं।

इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठी, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेनारसन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अर्चिता सिंह, कमिशनर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज सुश्री रेखा मोहन, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) श्री धीरज पारेख, सड़क एवं भवन तथा शहरी विकास विभाग के सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित रहे

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

वायु प्रदूषण से हलकान दिल्ली

दिल्ली में वायु प्रदूषण दिल्ली में बृहस्पतिवार को भी घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वजीरपुर में सबसे ज्यादा 460 तक दर्ज किया गया। सबसे कम भी पूसा में 302 है। इस तरह 37 निगरानी वेंदों में से 27 निगरानी वेंदों में एक्यूआई स्तर अत्यन्त गंभीर था। वायु प्रदूषण की इस स्थिति से परेशान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चन्द्रकर ने बृहस्पतिवार को वकीलों से आग्रह किया कि स्थिति हबाहुत गंभीररूह है, मत आइए कोर्ट, घर से ही वीडियो कांफ्रॉसिंग से मुकदमों की पैरवही कीजिए। दिल्ली को प्रदूषण का शहर बताकर वकीलों से बाहर न निकलने का आग्रह करना वेंद और दिल्ली दोनों ही सरकारों के लिए बहुत बड़ा व्यंग है। वेंद सरकार बड़े गर्व से दावा करती है कि दिल्ली की असली आर्थारिटी यानि सत्ता उपराज्यपाल, वेंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से चलाते हैं, किन्तु अब जब दिल्ली में पर्यावरण संकट भयंकर रूप से बच्च्यों, वृद्धजनों, सांस के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और वेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) लगातार बढ़ती एक्यूआई की स्थिति से सरकारों को आगाह कर रहा है किन्तु दुर्भाग्य से जितना प्रयास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और यही कारण है कि दिल्ली बिल्चुल गैस चैम्बर बन चुकी है। दरअसल वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमारी यानि सरकार और समाज दोनों में से किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही नहीं है। आज दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भले ही वेंद और राज्य सरकार को ठहराया जा रहा है किन्तु स्थानीय निकायों की घोर लापवाही भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यदि स्थानीय निकाय ने शुरू से जिम्मेदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो कदाचित्त दिल्ली में वायु प्रदूषण के विकराल स्थिति के सामने केन्द्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण के बढ़ते संकट के सामने इतनी निःसहाय न दिखती। दिल्ली में तमाम पर्यावरण संबंधी एनजीओ और विशेषज्ञ सरकारों को सावधान करते रहते हैं किन्तु प्रशासनिक अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर उन उपायों को लागू करने से बचते रहते हैं जिनकी वजह से आज एक्यूआई सरपट दौड़ लगा रहा है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में औद्योगिक संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषणों को विनियंत्रित करने का अधिकार, वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने तथा उत्सर्जन के लिए परमिट पूरी तरह प्रबंधनों का पालन करते हुए देने की प्रवि्या का उल्लेख है किन्तु वेंद और राज्य सरकारें इस अधिनियम को लागू कर पाने में असमर्थ साबित हो चुकी हैं। कारण वुछ भी हो सच तो यही है कि वायु प्रदूषण के सामने सारे उपाय बेकार साबित हुए। बहरहाल वेंद सरकार को चाहिए कि तत्काल दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय को साथ लेकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारणों से निपटे और वायु को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन एवं कटाई पर रोक लगाएं तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल छिड़काव, वृक्षिम वंषात इत्यादि को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब वेंद व राज्य सरकारें आपातकालीन मुहिम चलाएं और समाज के सभी वर्गों को शामिल किया करें। इसके लिए मीडिया में विज्ञापन और लोगों को जागृत किए जाने की जरूरत हैं। एक बार यदि जनता ने ठान लिया कि वह अपने आसपास के लोगों को वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जागरूक करेगी तो निर्गति रूप से स्थिति में सुधार की असीम संभावनाएं हैं।

बोफा का अडानी समूह पर 'ओवरवेट' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू, फंडिंग एक्सेस मजबूत का भरोसा, समझें गेम

(जीएनएस)। अमेरिकी निवेश बैंक 'बैंक ऑफ अमेरिका' (बोफा) ग्लोबल रिसर्च ने अडानी समूह पर क्रेडिट कवरेज शुरू करते हुए उसके कई यूएस डॉलर बॉन्ड्स पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है। रिपोर्ट में समूह की मजबूत वित्तीय स्थिति, बेहतर डीलीवरेजिंग (ऋण कम करने की प्रक्रिया) और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एक्सेस को हाइलाइट किया गया है, जो 2023 की हेनगे शॉर्ट-सेलर रिपोर्ट और 2024 के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) के अभियोग जैसे विवादों के बीच एक सकारात्मक संकेत है। बोफा ने अडानी को 'उच्च गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट' करार दिया, जो एशियाई समकक्षों की तुलना में आकर्षक वैल्यूएशन ऑफर करता है। लेकिन रिपोर्ट ने जोखिमों – जैसे उच्च कोस का प्रतिकूल फैसला या गवर्नेंस आरोपों का फिर से उभरना – पर भी चेतावनी दी है। आइए, इस रिपोर्ट की गहराई में उतरें, जो अडानी शेयरों को बूस्ट दे रही है और बाजार में नए निवेश के द्वार खोल रही है।

अल्लि ऋद्धष्ठर २ इङ्ग्ल्लरि दीद२

अडानी समूह की वित्तीय मजबूती: EBITDA 10.5 अरब डॉलर, डेट-टू-EBITDA रेशियो में सुधार

बोफा की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी समूह का वित्त वर्ष 2025 का

EBITDA (अर्निंस बिफोर इंटररेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन) ₹89,800 करोड़ (लगभग 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया, जिसमें 80% से ज्यादा योगदान उसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस – जैसे पोर्ट्स, यूटिलिटीज और रिन्यूएबल एनर्जी – से आया। समूह का शुद्ध ऋण-से-EBITDA अनुपात F 19 के 3.8x से घटकर 2.6x हो गया, जो डीलीवरेजिंग की मजबूत रणनीति को दर्शाता है।

रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना (25.72 कि.मी.) को मंजूरी दी रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री

रेलवे ने पंजाब के मुख्य सचिव को भूमि के शीघ्र अधिग्रहण हेतु पत्र लिखा परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को लाभ होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे

चंडीगढ़ :

रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना कुल 25.72 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹764.19 करोड़ है, जिसमें से ₹166 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित हैं, जो रेलवे द्वारा वहन किए जाएंगे।

आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं पश्चिम रेलवे के मध्य हुए समझौता ज़ापन के अंतर्गत तीन रेल कर्मचारियों के परिवार को को वित्तीय सहायता राशि का वितरण

(जीएनएस)।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पश्चिम रेलवे के मध्य हुए समझौता ज़ापन (टडब) के अंतर्गत भावनगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक की ओर से मृतक रेल कर्मचारियों के परिजनों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त समझौते की प्रमुख शर्तों, लाभों एवं बीमा सुरक्षा से संबंधित जानकारीयें विस्तार से साझा कीं। यह पहल रेलवेक कर्मकितियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मृतक कर्मचारी श्री नरेंद्रसिंह जे गोहिल, कार्यालय अधीक्षक, भावनगर टर्मिनस के

मतगणना से पहले चिराग पासवान ने किसे कहा-

(जीएनएस)। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। आने वाले 24 घंटों में तय हो जाएगा कि अगले 5 साल में बिहार में कौन राज करने वाला है। 11 -12 नवंबर की शाम को न्यूज चैनलों और एजेंसी की ओर से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, जिसमें से अधिकांश में कहा जा रहा है कि 'बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है।'

हालांकि राजद और कांग्रेस दोनों ने इसे ठुकराते हुए कहा कि 'शुक्रवार की सुबह सारे एग्जिट पोल को गलत साबित करेगी और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी।' इन्हीं दावों के बीच लोगों कि निगाहें खुद को 'पीएम मोदी का हनुमान' कहने वाले चिराग पासवन पर भी लगी हैं।

चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थीं लेकिन एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, ऐसे में अब

संक्षिप्त समाचार

कब और किस वक्त आएंगे बिहार चुनाव के परिणाम ? कहां देखें लाइव काउंटिंग ?

बिहार की राजनीति अब एक बड़े फैसले के सामने खड़ी है। 2025 के विधानसभा चुनावों की वोट गिनती शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। इस चुनाव में राज्य भर में मतदाताओं ने जबरदस्त भागीदारी दिखाई, और एमिजट पोल ने एनडीए की मजबूत वापसी का संकेत दिया है। अब हर नजर विधानसभा की 243 सीटों पर लगी है, क्योंकि आज के नतीजे अगले पांच साल के लिए बिहार की राजनीति का नक्शा तय करेंगे। क्या नीतीश कुमार अपनी लंबी कार्यकाल वाली सरकार को जारी रख पाएंगे।

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, कहा- 'भारत-अफगानिस्तान से एक साथ जंग के लिए तैयार'

दिल्ली, (जीएनएस)। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका देश पूर्वी सीमा पर भारत और पश्चिमी सीमा पर तालिबान के खिलाफ 'दो मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार' है। यह बयान 12 नवंबर, 2025 को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के एक दिन बाद आई, जिसमें 12 लोग मारे गए और 36 अन्य घायल हुए थे।

"दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार"— आसिफ का दावा

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, आसिफ ने कहा, "हम दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं। हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) दोनों का सामना

(जीएनएस)।

कैलिफोर्निया में 17,000 विदेशी ट्रक चालकों के कर्मशैथिल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में है। इस फैसले से भारतीय मूल के सैकड़ों ट्रक चालक प्रभावित हो सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका में ट्रक चालकों की कमी के दौरान काम का अंतर भरा था। साथ ही कई चालक गलत दिशा में ड्राइविंग करते हुए भी पकड़े गए हैं।

अवैध ट्रक चालकों से जुड़ी दुर्घटनाएं बनी वजह यह फैसला कई घातक सड़क दुर्घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें कुछ भारतीय अवैध ट्रक चालक भी शामिल थे। अधिकारियों ने पाया कि कई चालकों के लाइसेंस की वैधता अवधि उनके अमेरिका में रहने

की अनुमति से अधिक थी। इसी कारण इन्हें अवैध घोषित कर रद्द करने का फैसला लिया गया।

भारतीय मूल के चालकों पर सबसे ज्यादा असर राज्य ने यह नहीं बताया कि कौन से अप्रवासी प्रभावित होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय और भारतीय मूल के ट्रक चालकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लॉस एंजिल्स टाइम्स की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में भारतीय-सिख समुदाय को कैलिफोर्निया सहित पूरे अमेरिका में

ट्रक चालकों की कमी को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी।



कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने कहा कि ये लाइसेंस इसलिए अमान्य थे क्योंकि उनकी समाप्ति तिथि चालकों के अमेरिका में रहने की अवधि से आगे थी। एजेंसी एपी (अड) के मुताबिक, राज्य

जाने वाली है शरीफ मियां की कुर्सी! मुशर्रफ की राह पर आसिम मुनीर, जल्द बनेंगे अगले तानाशाह!

फील्ड मार्शल असीम मुनीर आज पाकिस्तान के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सैन्य शासक के रूप में उभरे हैं। पाकिस्तान के संविधान में हुए 27वें संशोधन ने उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बना दिया है, जिसके तहत वे तीनों सशस्त्र बलों, न्यूक्लियर फोर्सेस और सेना के प्रमुख के रूप में असीमित कार्यकाल के साथ कार्यरत हैं।

यह पद उन्हें नागरिक राजनीति से ऊपर एक आजीवन सैन्य तानाशाह के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने अपने द्वारा घोषित "कठोर राज्य" की अवधारणा के अंतर्गत पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।



बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकवाद के नए रास्ते बना रहा लश्कर-ए-तैयबा, इंटेलिजेंस ने क्या वॉर्निंग दी?

(जीएनएस)।

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ढाका और इस्लामाबाद के बढ़ते सैन्य संबंधों के जरिए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) भारत में घुसपैठ का एक नया मार्ग खोलने की कोशिश में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छिड़ का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की योजना बना रहा है, जिसमें बांग्लादेश को लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ढाका-इस्लामाबाद की नजदीकियों से दिल्ली में चिंता

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब ढाका और इस्लामाबाद के बीच अचानक संबंध मजबूत हो रहे हैं।

1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन हाल के हफ्तों में उच्च-स्तरीय सैन्य और राजनीतिक मुलाकातों ने नई दिल्ली में गहरी चिंता पैदा कर दी है।

हाल ही में, पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने ढाका का चार दिवसीय दौरा किया। लगभग उसी समय, पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत पीएनएस सैफ चटगांव बंदरगाह पर लंगर डाले हुए था। यह 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद पहली बार हुआ है कि कोई पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेशी जलक्षेत्र में आया हो। इस कदम को

रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

"हाफिज सईद भारत पर हमला



करेगा"

भारत की चिंता और बढ़ गई जब पाकिस्तान के खैरपुर तामेवाली से एक वायरल वीडियो सामने आया। इसमें छिड़ का सीनियर कमांडर सैफुल्ला सैफ यह घोषणा करते दिखे कि "हाफिज

सईद बांग्लादेश के माध्यम से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।"

खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस दावे को अब केवल बयानबाजी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर पाकिस्तान-आधारित चरमपंथी नेटवर्कों की हालिया गुप्त गतिविधियों को देखते हुए।

हाफिज सईद का सहयोगी जहीर बांग्लादेश यात्रा पर रिपोर्ट्स के अनुसार, हाफिज सईद का करीबी सहयोगी अल्लामा इब्निसाम इलाही जहीर ने अक्टूबर के अंत में गुप्तगुप्त तरीके से बांग्लादेश का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजशाही और चापैनवाबगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में कट्टरपंथी समूहों से मुलाकात की।

परिवहन विभाग ने भी इसकी पुष्टि की कि लाइसेंस की वैधता कानूनी रहने की अवधि से अधिक थी, जिससे उन्हें रद्द करना पड़ा।

हालिया दुर्घटनाओं ने बढ़ाई चिंता पिछले महीने कैलिफोर्निया में एक भारतीय अवैध ट्रक चालक की वजह से हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद ट्रक चालकों में अवैध ड्राइविंग का मुद्दा फिर चर्चा में आया और यह मामला ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेटिक सरकार के बीच विवाद का विषय बन गया।

अंग्रेजी दक्षता और फंडिंग विवाद अधिकारियों ने बताया कि 2025 में 7,000 अमेरिकी ट्रक चालकों को अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में फेल होने पर सेवा से बाहर किया गया।

लाल किला धमाके पर क्या बोला अमेरिका? किस बात के लिए की भारतीय एजेंसियों की तारीफ?

(जीएनएस)।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके को "स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला" करार दिया है। उन्होंने बुधवार को ऋ विदेश मंत्रियों की बैठक समाला होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। यह धमाका 10 नवंबर, 2025 की शाम को हुआ था, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

दिल्ली ब्लास्ट को बताया आतंकी हमला

मार्को रुबियो ने भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया की भी सराहना की, जिसे अब भारत ने "राष्ट्र-विरोधी ताकती" द्वारा किए गए "आतंकवादी 'काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो होगा नेपाल जैसा हाल"—आरजेडी नेता ने दी खुलेआम धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से ठीक पहले राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ गया है। एक तरफ जहां एनडीए खेमे में जीत की तैयारी और पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। वहीं

दूसरी ओर आरजेडी ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का धमाकेदार बयान सामने आया है, जिसने माहौल और गरमा दिया है।

❖ राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, "इस बार बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है।

बिग बॉस से बेघर हुए मृदुल तिवारी, सोशल मीडिया पर फैस ने उठाए मेकर्स पर सवाल

(जीएनएस)।

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 के इस हफ्ते का माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जब मिड-वीक एक्विशन में मृदुल तिवारी को घर से बाहर कर दिया गया। मृदुल, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, शांत स्वभाव और समझदारी से दर्शकों का दिल जीता था, अचानक बाहर हो गए। इस फैसले ने न केवल घरवालों बल्कि दर्शकों को भी हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने इसे "अन्यायपूर्ण" एक्विशन बताया और मेकर्स पर सवाल उठाए।

बहन प्रगति का मेकर्स पर गंभीर आरोप

मृदुल के बाहर होने के तुरंत बाद उनकी बहन प्रगति तिवारी ने एक वीडियो शेयर कर शो के मेकर्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह एलिमिनेशन "जनता के वोट" से नहीं



पड़ोसी राज्यों की ओर रख करना पड़ता था। लेकिन आज, पच्चीस वर्षों के भीतर उत्तराखंड ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पूरे देश के लिए उदाहरण बन गई हैं।

मतदान के बाद पार्टी कार्यालयों में सियासी सन्नाटा, अब निगाहें 14 नवंबर के नतीजों पर

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान अब संपन्न हो चुका है। अब पूरे राज्य की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले मतगणना और नतीजों पर टिकी हैं। चुनाव प्रचार की गहमागहमी, नारों की गूंज और रोड शो की भीड़भाड़ के बीच जो माहौल कई महीनों से पूरे बिहार में देखने को मिल रहा था, वह अब ठहर गया है।

जहां पहले नेताओं की आवाजें चौक-चौराहों तक गूंज रही थीं, वहीं अब राजनीतिक गलियारों में एक गहरी शांति और इंतजार का माहौल है। गुरुवार, 13 नवंबर की सुबह पटना की सड़कों पर रौनक अब नदारद थी, जो पिछले कई

हफ्तों से लगातार बनी हुई थी।

चुनावी शोर के बाद सन्नाटा थम गया है और पार्टी कार्यालयों के बाहर एक अलग सी खामोशी दिखाई दे रही है। कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा



- चारों प्रमुख दलों के प्रदेश कार्यालयों का नजारा इस बार बदला-बदला था। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में न तो रणनीतिक बैठकों की भागदौड़ थी, न ही समर्थकों की भीड़।

घटना" के रूप में पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला था और यह अत्यधिक विस्फोटक सामग्री से लदी कार थी, जिसमें विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए।"

वाशिंगटन ने बताया भारत को समर्थन

वाशिंगटन प्रशासन ने नई दिल्ली को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि, रुबियो ने भारतीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय जांचकर्ता "इन जांचों में सक्षम और पेशेवर हैं।" उन्होंने कहा, "हमने मदद की पेशकश

की है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, और वे



अच्छा काम कर रहे हैं।"

"भारतीय जांचकर्ता सतर्क और प्रोफेशनल" अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, "हमें संभावित खतरे के बारे में

संदिग्धों ने ऐसे रची थी सीरियल ब्लास्ट की खौफनाक साजिश, 32 कारों में थी ब्लास्ट की प्लानिंग

(जीएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी साजिश का पदांश किया

है। गुरुवार, 13 नवंबर को खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि यह धमाका एक बड़े सीरियल ब्लास्ट की साजिश का हिस्सा था, जिसमें कुल 32 पुरानी गाड़ियों में बम लगाकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक साथ विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी।

इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, और जांच के बाद यह साफ हो गया है कि यह साजिश का एक हिस्सा था, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी।

खुफिया एजेंसियों से मिली

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अटक के हवाले से सूत्रों ने बताया कि अब तक



जांच में यह सामने आया है कि एक 20 और एक इकोस्पॉर्ट गाड़ी को हमले के लिए तैयार किया जा रहा था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक,20 और इकोस्पॉर्ट के बाद यह जानकारी मिली कि 32 और पुरानी गाड़ियों को

जिन गलियारों में कल तक नारे और भाषणों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है।

चाय की दुकानों पर एंकिजट पोल की चर्चा

पटना की गलियों और दुकानों पर अब नेताओं की बयानबाजी की चर्चा नहीं, बल्कि मतदान प्रतिशत और एंकिजट पोल के आंकड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग अपने-अपने अंदाज में नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं कहीं

लोग नीतीश कुमार की वापसी की बात कर रहे हैं तो कहीं तेजस्वी यादव की संभावनाओं पर चर्चा गर्म है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी यही नजारा दिख रहा है।

पता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए। वे इस चल रही जांच को मापे हुए, सतर्क और प्रोफेशनल तरीके कर रहे हैं।" उन्होंने विश्वास जताया कि "जब भारतीय जांचकर्ताओं के पास तथ्य होंगे, वे उन्हें सार्वजनिक रूप से जारी करेंगे।"

अमेरिकी दूतावास ने भी जताई संवेदनाएं

इससे पहले, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी इस धमाके पर एक आधिकारिक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया, "हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने पिछली रात नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट में अपनों को खो दिया।

बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकवाद के नए रास्ते बना रहा लश्कर-ए-तैयबा, इंटेलिजेंस ने क्या वॉर्निंग दी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन गाड़ियों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ा कर कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट (समानांतर धमाके) करने की साजिश थी। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां हैरान हो गई हैं

और अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन 32 गाड़ियों में से कुछ पहले ही तैयारी की जा चुकी थी।

जांच में अब फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का बायज हॉस्पिटल भी शक के घेरे में आ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के

अग्निवीर भर्ती रैली, जानिए कब से और कहां, क्या दस्तावेज हैं जरूरी
उत्तराखंड में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गढ़वाल क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए लैंसडाउन

गढ़वाल राइफल में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली कोटद्वार में आयोजित की जाएगी।

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम जारी हो गया है। रैली आगामी 15 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक जीबीएस कैंप (कोटद्वार) में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी किसी भी समस्या के मामले में एआरओ लैंसडाउन यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। समय-समय पर अपने लॉगिन अकाउंट के माध्यम से JJA यानी Join Indian Army की वेबसाइट https://www.joinindianarmy.nic.in/ को चेक करते रहें।

साइट से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7456874057 जारी किया गया है।

उम्मीदवार को प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, तीन फोटोकॉपी और सभी मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 3:00 बजे तक रैली स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर ओटीपी आधारित सत्यापन के लिए आधार कार्ड एवं जेआईए वेबसाइट के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर लाना होगा।